वर्ष: 7 अंक: 03

1-15 अगस्त, 2026 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

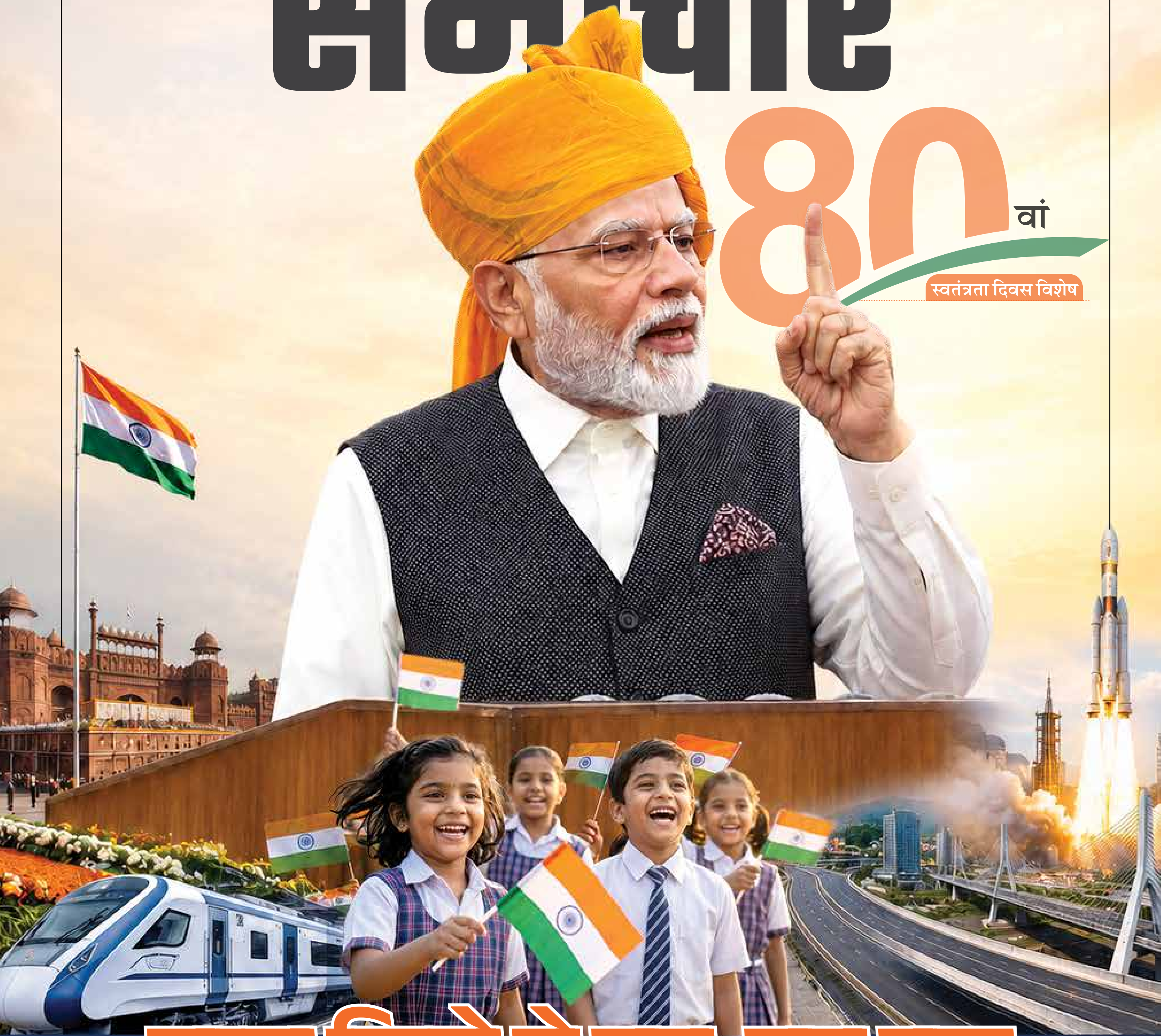

80वां

स्वतंत्रता दिवस विशेष

लाल किले से जन-जन तक विकसित भारत की यात्रा

लाल किले की प्राचीर से गूंजा हर संकल्प आज साकार रूप ले रहा है। बीते 12 वर्षों की उपलब्धियां बताती हैं कि कैसे 'राष्ट्र प्रथम' की भावना विकसित भारत @2047 की बन रही है नींव...

हमें फॉलो करें @NISPIBIndia

मेघालय के रूट ब्रिज

धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान

मेघालय की पहचान बादलों, खूबसूरत नजारों और वहां के लोगों के अपनेपन से है। मेघालय की एक और विशेषता है - रूट ब्रिज जो कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते। इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबड़ के पेड़ों की जड़ों को धीरे-धीरे दिशा देकर इसे जल-धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। ये जीवित ब्रिज, समय बीतने के साथ और मजबूत हो जाते हैं जिनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति है गहरा सम्मान...

UNESCO

देश की धरोहर रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल कराने के लिए अब भारत ने आवेदन किया है।

"आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देख-रेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

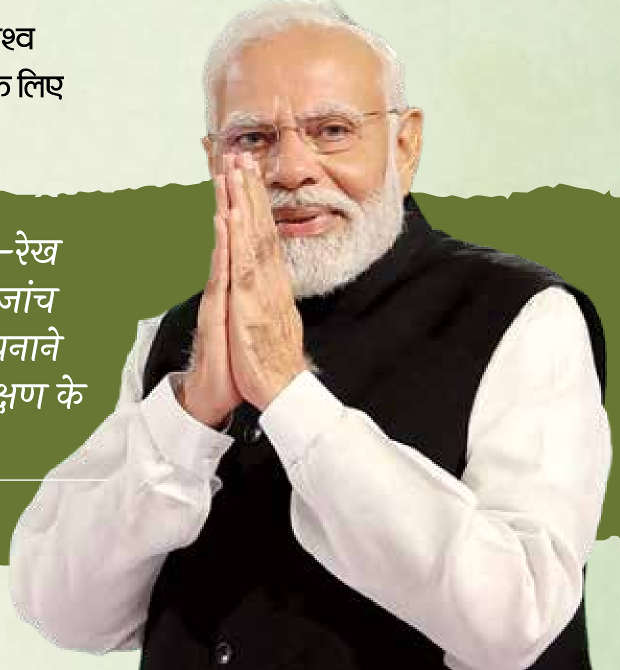

न्यू इंडिया
समाचार

वर्षः 7, अंकः 03 | 1-15 अगस्त, 2026

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा
प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

मुख्य सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
पवन कुमार

सहायक सलाहकार संपादक
अखिलेश कुमार
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी)
रजनीश मिश्रा (अंग्रेजी)
नदीम अहमद (उर्दू)

सीनियर डिजाइनर
फूलचंद तिवारी

डिजाइनर
अभय गुप्ता
सत्यम सिंह

13 भाषाओं में उपलब्ध न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने के लिए क्लिक करें।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

न्यू इंडिया समाचार के पुराने अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

न्यू इंडिया समाचार के बारे में लगातार अपडेट के लिए फॉलो करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...

'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प से सशक्त होता नया भारत

इस 15 अगस्त को जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब हर भारतवासी के मन में एक ही संकल्प गूंज रहा है... आजादी के 100वें वर्ष में विकसित भारत की सिद्धि। बीते 12 वर्ष में आजादी का यह जश्न बना है विकास यात्रा का महोत्सव... | 10-30

प्रधानमंत्री का आलेख

भारत की एकता और प्रगति के लिए
समर्पित एक जीवन

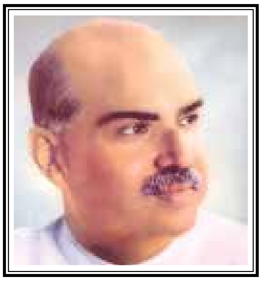

पीएम मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अमूल्य योगदान का स्मरण करते हुए लिखा आलेख | 6-8

समाचार सार | 4-5

व्यक्तित्व : प्रो. एमएस स्वामीनाथन
जिन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा को बनाया जीवन का ध्येय | 9

सेमीकॉन 2.0 और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय | 31

दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता भारत
पीएम मोदी ने राजस्थान को दी विकास की सौगातें | 32-33

प्रगति और रणनीतिक तालमेल का नया अध्याय
जापान की पहली महिला पीएम ताकाइची सनाए की भारत यात्रा | 36-37

वैश्विक रिश्तों को नई उड़ान
पीएम मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा | 38-41

भारतीय महिला क्रिकेट : स्वर्णिम भविष्य की दमदार उद्घोष
लॉर्ड्स मैदान के पहले अतरराष्ट्रीय महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत की जीत | 42

नेक्स्ट जेन टेक क्रांति...
भारत में सेमीकंडक्टर का नया युग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन किया | 34-35

प्रकाशकः कंचन प्रसाद, महानिदेशक, सीबीसी (केंद्रीय संचार ब्यूरो) | **पत्राचार और ईमेल के लिए पताः** कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003. **ईमेल- response-nis@pib.gov.in आर. एन. आई. नंबर DELHIN/2020/78812**

संपादक की कलम से...

80वां स्वतंत्रता दिवस विशेष : आत्मनिर्भरता से साकार हो रहा विकसित भारत का लक्ष्य

सादर नमस्कार

15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुआ, परंतु सच्चे अर्थों में स्व का तंत्र विकसित करने के लिए राष्ट्र को दशकों तक निरंतर प्रयास करने पड़े। अब, जब भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की ओर अग्रसर है, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि देश ने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। बीते 12 वर्षों में अनेक ऐसे प्रयास हुए जिन्होंने भारत की आत्मनिर्भर और गौरवशाली पहचान को नई ऊंचाई दी है।

नए संसद भवन का निर्माण, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने, इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने, नए आपराधिक कानून लाने, नए नौसेना ध्वज को अपनाने, रेल बजट को वार्षिक बजट में समाहित करने, ब्रिटिश शासनकाल में प्रतिबंधित साहित्यिक कृतियों के पुनर्प्रकाशन तथा बजट प्रस्तुति में पारंपरिक 'बही खाता' के प्रयोग जैसे कदमों ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई पहचान दी है। बजट प्रस्तुति के समय और तिथि में परिवर्तन भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। ये सभी प्रयास वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रयासरत हैं। न्यू इंडिया समाचार का यह विशेष अंक इसी भावना को समर्पित है।

लोकतंत्र की सुदृढ़ता से लेकर आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय, विज्ञान-तकनीक में आत्मनिर्भरता, रक्षा क्षेत्र में सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, बुनियादी ढांचे के कायाकल्प, कृषि व ग्रामीण विकास, शिक्षा-कौशल विकास, नारी नेतृत्व, खेल जगत की उपलब्धियां, विदेश नीति में बढ़ती वैश्विक साख, पर्यावरण संरक्षण तथा सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत के संवर्धन तक, 80 चुनी हुई उपलब्धियां 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत की उस यात्रा को रेखांकित करती हैं जो अतीत के गौरव से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर अग्रसर है। यह अंक केवल बीते 12 वर्ष की स्मृतियों का दस्तावेज नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए एक आह्वान भी है कि आइए अपने राष्ट्र के निर्माण में सारथी बनें।

इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में देश की खाद्य सुरक्षा को जीवन का ध्येय बनाने वाले एमएस स्वामीनाथन, गुजरात एवं राजस्थान को विकास की सौगातें सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान दर्शाने वाले मेघालय रूट ब्रिज और बैक कवर पर हर साल 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपने सुझाव हमें भेजते रहें।

धीरेन्द्र

(धीरेन्द्र ओझा)

हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

आपकी बात...

सामाजिक विकास से जुड़ी कहानियों का एक बेहतरीन तालमेल

'न्यू इंडिया समाचार' का लेटेस्ट एडिशन शेयर करने के लिए धन्यवाद। मैंने इस इश्यू को बहुत दिलचस्पी के साथ पढ़ा। इसके संपादकीय में योग को भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और एक ग्लोबल मूवमेंट के तौर पर इसके विकास को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। जिस तरह से यहां व्यक्ति से परिवार, समाज, देश और आखिर में पूरी मानवता तक के सफर को जोड़ा गया है, वह बहुत समझदारी भरा एवं प्रेरणा देने वाला है। इस इश्यू में गवर्नेंस, पॉलिसी, सामाजिक विकास और लोगों से जुड़ी कहानियों का एक बेहतरीन तालमेल है।

vivek.pandey@timesofindia.com

समाज हित में किए जा रहे कार्यों की समग्र प्रामाणिक जानकारी

यह पत्रिका वास्तव में देश के विकास कार्यों का सटीक लेखा-जोखा है। प्रशासन की नीतियों से आम जनता एवं लोक सेवकों को रूबरू करवाना बहुत आवश्यक है। इससे शासन-प्रशासन द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की समग्र प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। मै इस पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

कामता प्रसाद प्रजापति
kvkpprajapati@gmail.com

सरल और रोचक भाषा

मेरी राय में 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका नए भारत की प्रगति का आईना है। यह केवल समाचारों का संकलन नहीं, बल्कि देश के विकास की कहानी को सरल और रोचक भाषा में बताने का सशक्त माध्यम है। जुलाई 2026 के अंक की कवर स्टोरी सबसे खास है। इसमें नए भारतीय कानूनों के 2 साल पूरे होने का जिक्र है।

औपनिवेशिक कानूनों को हटाकर 'नागरिक प्रथम' की सोच को अपनाना यह दिखाता है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो चुका है। इस अंक में राष्ट्रीय गौरव के कई पल हैं। डिजिटल इंडिया के 11 साल, जोजिला सुरंग का ऐतिहासिक ब्रेक-थ्रू और 3 करोड़ 'लखपति दीदी' का लक्ष्य पूरा होना। इन सभी उपलब्धियों को तथ्यों के साथ बहुत अच्छी तरह बताया गया है। कुल मिलाकर, यह पत्रिका प्रेरणादायक है। इसे पढ़कर देश की ताकत और भविष्य की दिशा समझ आती है। मेरा मानना है कि हर भारतीय तक यह पत्रिका पहुंचनी चाहिए।

कमल वर्मा, kmlksr0@gmail.com

गवर्नेंस और राष्ट्र-निर्माण के बारे में व्यापक नजरिया

विनीता सोरेन की प्रेरणादायक यात्रा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले, प्रगति (PRAGATI), रोजगार मेला और प्रधानमंत्री के अंतरराष्ट्रीय दौरों की कवरेज खासतौर पर पसंद आई। ये सभी मिलकर पाठकों को आज की गवर्नेंस और राष्ट्र-निर्माण के बारे में एक व्यापक नजरिया देते हैं। इतनी अच्छी तरह से तैयार की गई पत्रिका को लगातार लाने के लिए आपको और पूरी एडिटोरियल टीम को बधाई। मैं आगे भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण एडिशन पढ़ने का इंतजार करुंगा।

ashishprabhatmishra@gmail.com

राष्ट्रीय नीतियों पर दी गई जानकारी बहुत उपयोगी

मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका की नियमित पाठक हूं। इस पत्रिका में सरकारी योजनाओं व राष्ट्रीय नीतियों पर दी गई जानकारी मुझे बहुत उपयोगी लगती हैं।

अनुष्का बर्दिया
anushkabardiya@gmail.com

पत्राचार और ईमेल के लिए पता: कमरा संख्या-1077, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस...

भारत शांति का पक्षधर है लेकिन भारतीय सीमा में अशांति फैलाने वाले या नागरिकों को हानि पहुंचाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ता नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत गृह मंत्रालय ने 23 और व्यक्तियों को 'आतंकवादी' घोषित किया है। इन 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं। यह सभी पाकिस्तान और **PoJK** से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत और यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये घोषित आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकी हमले, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार से घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद करने, फंड जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती करने में शामिल हैं। सरकार का यह निर्णय आतंकवादियों के धन जुटाने के तंत्र, आवाजाही, भर्ती क्षमता और आतंक से जुड़ी गतिविधियों को रोककर आतंकी इकोसिस्टम को खत्म करने में अहम सिद्ध होगा।

पौधारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

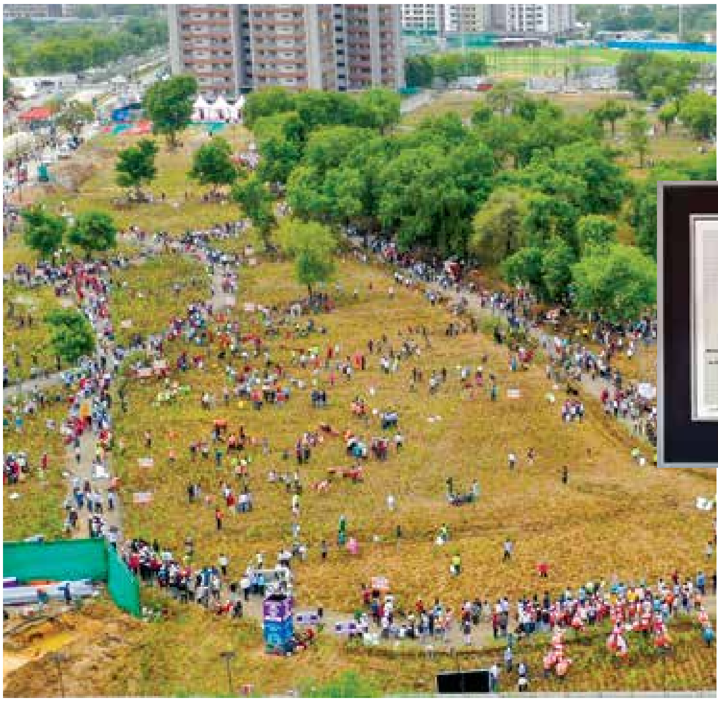

पर्यावरण संरक्षण आज देश में जन-आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान ने देशभर के करोड़ों नागरिकों को प्रकृति संरक्षण के इस महायज्ञ से जोड़ने का कार्य किया है। इसी कड़ी में जुलाई के पहले पखवाड़े में गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र ने मियावाकी पद्धति के तहत एक घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधारोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है।

गांधीनगर के नागरिकों ने 'सार्वजनिक वृक्षारोपण अभियान' के तहत 1.26 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया है। इनमें 404 सार्वजनिक स्थलों पर करीब 1.16 करोड़ पौधों का रोपण किया गया, जबकि क्षेत्र के नागरिकों ने अपने निजी परिसरों में 11 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।

उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास-न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत तय किए मानकों को पूरा कर उत्तराखंड देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित साक्षरता मानकों की पूर्ति के बाद 8 जुलाई 2026 को इसकी घोषणा की गई। मई, 2025 में मिजोरम सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम भी पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। उत्तराखंड ने नई नीति के तहत पूर्ण साक्षर राज्य बनकर शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है।

भारतीय फलों का स्वाद, बनी दुनिया की पसंद

भारत के प्रीमियम फलों का स्वाद अब दुनिया की पसंद बन रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड की लीची की खेप इटली तो तेजपुरी लीची दुबई की पसंद बना है। किसानों के लिए बेहतर दाम, नए बाजार और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का काम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (**APEDA**) कृषि उत्पादों के निर्यात की व्यवस्था से कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू एवं कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंटरोज प्लम के पहले एक्सपोर्ट शिपमेंट की व्यवस्था भी **APEDA** ने की। यह प्रगति प्रीमियम भारतीय फलों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय डिमांड को दर्शाती है।

भारत का स्वाद अब खेतों से उड़ान भरकर दुनिया की थाली में पहुंच रही है। जम्मू-कश्मीर की शोपियां और पुलवामा की प्रीमियम अरेको चेरी और सेंटरोज प्लम की पहली निर्यात खेप अबू धाबी और दुबई के लिए रवाना की गई। यह उपलब्धि भारतीय फलों की वैश्विक पहचान को और मजबूत करने के साथ जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र के लिए नए अवसर लेकर आई है।

आईएनएस महेंद्रगिरि... समुद्री सीमा का नया रक्षक

भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 24 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा नौसेना सुनिश्चित करती है। यही वजह है कि वर्तमान केंद्र सरकार नौसेना को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसी कड़ी में 11 जुलाई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौ सेना के बेड़े में भारत में निर्मित उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट 'आईएनएस महेंद्रगिरि' को शामिल किया।

आईएनएस महेंद्रगिरि अग्रिम पंक्ति का विशाल युद्धपोत है। यह सतह से सतह और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ ही स्वदेशी रॉकेट एवं टॉरपीडो लॉन्चर से लैस है। यह जहाज वायु रक्षा, पनडुब्बी-रोधी युद्ध और निगरानी के साथ-साथ सहायता एवं आपदा राहत अभियानों को पूरा करने में भी सक्षम है। यह युद्धपोत 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री और 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के योगदान से निर्मित है। पूर्वी बेड़े में शामिल होने के बाद यह युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री युद्ध क्षमता, परिचालन पहुंच और उपस्थिति को काफी मजबूत करेगा। ▪

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित एक जीवन

भारत की एकता के सूत्रधार, अखंड भारत के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती को केंद्र सरकार दो वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। वर्ष 2025 में 6 जुलाई को यह शुरू हुआ था जो 6 जुलाई 2027 तक चलेगा। इस वर्ष उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. मुखर्जी के अमूल्य योगदान का स्मरण करते हुए आलेख लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का उनका विजन राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दे रहा है नई ऊर्जा...

राष्ट्रवाद और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए 6 जुलाई का दिन बहुत ही विशेष है जब हम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म-जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन साहस और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में विद्वता, जनसेवा और उच्च नैतिक मूल्यों का अद्भुत संगम था। आधुनिक भारत के कुछ ही नेताओं में इतने सारे गुण एक साथ देखने को मिलते हैं।

श्यामा प्रसाद जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था, जहां उन्हें सुख-सुविधाओं से भरपूर जीवन आसानी से मिल सकता था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी की गिनती अपने समय के महान शिक्षाविदों में होती थी। लेकिन तमाम सुविधाओं के बावजूद श्यामा प्रसाद जी ने त्याग और राष्ट्रसेवा का मार्ग चुना। उनका दृढ़ विश्वास था कि चाहे अंग्रेजी शासन का विरोध हो, सांप्रदायिकता से लड़ाई हो या मानवीय संकटों का सामना, वे अपने समय की इन चुनौतियों के सामने मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकते। इस सफर में उन्हें कई गहरे व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े। पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया और बाद में पत्नी का भी निधन हो गया। लेकिन इन दुखद परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका संकल्प और सशक्त हुआ, राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण और गहरा होता गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। जेल और नजरबंदी भी उन्हें रास्ते से डिगा नहीं सकी। जब नजरबंदी के दौरान उनका निधन हुआ, तब वे उन अनगिनत लोगों से बहुत दूर थे, जिनके लिए वे जीवनभर संघर्ष करते रहे। इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब किसी व्यक्ति का सर्वोच्च बलिदान राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डॉ. मुखर्जी का बलिदान भी ऐसा ही था। आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि डॉ. मुखर्जी ने उस उद्देश्य के लिए अपना बलिदान दिया, जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। दशकों बाद, साल 2019 में आर्टिकल 370 और 35(A) को हटाया जाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी।

डॉ. मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसके लिए उन्होंने मजबूत संस्थानों का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं बनाईं, जो उस समय की सोच से काफी आगे थीं। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए, जो राष्ट्रहित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप थे। शिक्षाविदों के एक सम्मेलन में डॉ. मुखर्जी ने कहा था, "शिक्षण संस्थानों को केवल बाबू या कम वेतन वाले कर्मचारी तैयार करने की फैक्ट्री समझना गलत है। हमें विद्यार्थियों को ऐसे तैयार करना होगा ताकि वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें। हमारी स्वशासी संस्थाओं जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स, प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो सकें। इसके साथ ही वे वित्त, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकें।"

कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने नेतृत्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें लाइब्रेरी की सुविधाओं में सुधार, विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा देना, ऐतिहासिक वस्तुओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और कृषि से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करना शामिल था। उन्होंने खेलकूद, टीचर्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट वेलफेयर जैसे क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया। विद्यार्थियों में अपनी यूनिवर्सिटी के प्रति गर्व की भावना विकसित हो, इसके लिए उन्होंने 24 जनवरी को विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस मनाने की परंपरा शुरू की। उन्होंने गुरुदेव टैगोर से विश्वविद्यालय के लिए एक गीत लिखने का अनुरोध भी किया था।

उनके जीवन के बाद के वर्षों में इस भावना का एक और उदाहरण तब देखने को मिला, जब उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का निर्णय लिया। उस समय देश में हर तरफ कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था। ऐसे में उन्होंने महसूस किया कि देश को एक ऐसे नए विकल्प की बहुत जरूरत है, जो भारत की प्रगति की बात भी करे और हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा रहे। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का चुनाव चिह्न 'दीपक' यानि मिट्टी का दीया रखा गया। एक अकेला दीया देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन उसमें अपने आसपास के गहरे से गहरे अंधकार को मिटाने की अद्भुत शक्ति होती है। जनसंघ ने अपने सक्रिय काल में और उसके बाद भी बिल्कुल यही किया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्यकाल बेहद अहम रहा। उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में याद किया जाता है, जिनका विजन बहुत विराट था। वे उद्योग को नए-नए आजाद हुए भारत के लोगों में सम्मान, अवसर और आत्मविश्वास का संचार करने का सशक्त माध्यम मानते थे। वे वेल्थ और वैल्यू क्रिएशन के महत्व को भली-भांति समझते थे। उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और मजबूत औद्योगिक नीति जैसी ऐतिहासिक पहल की। इसके माध्यम से आधुनिक औद्योगिक भारत की नींव रखी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत के पारंपरिक सामर्थ्य की कभी उपेक्षा न हो। वे हथकरघा, कुटीर उद्योग, कारीगरों और कपड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के हितों के भी प्रबल समर्थक थे।

यहां मैं अपना एक निजी अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट विजन के साथ जिस सिंदरी संयंत्र की स्थापना के लिए डॉ. मुखर्जी ने अथक प्रयास किए थे, उसकी कई दशकों तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने घोर उपेक्षा की। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार को उसके पुनरुद्धार का सौभाग्य मिला। उस कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरे सार्वजनिक जीवन के सबसे विशेष और अविस्मरणीय क्षणों में से एक बन गया।

भारत की प्राचीन परंपरा सदियों से संवाद और विचार-विमर्श

प्रधानमंत्री का आलेख पढ़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।

का सम्मान करती आई है। डॉ. मुखर्जी इस लोकतांत्रिक भावना के सशक्त प्रतीक थे। उन्होंने पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होना इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में राष्ट्र निर्माण का दायित्व राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है। उन्होंने पूरी निष्ठा और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन जब उन्हें लगा कि राष्ट्रीय महत्व के कुछ प्रश्नों पर देशहित में अलग मार्ग अपनाना आवश्यक है, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उस राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसे वे राष्ट्र के लिए आवश्यक मानते थे।

75 वर्ष पहले पंडित नेहरू पहला संविधान संशोधन लेकर आए। इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा प्रहार माना गया। तब डॉ. मुखर्जी इसके सबसे मुखर आलोचक रहे थे। वे भली-भांति समझ चुके थे कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। समय के साथ उनकी यह आशंका सही साबित हुई। जो पार्टी 75 वर्ष पहले पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी, उसी ने 1975 में देश पर आपातकाल थोपा। इतना ही नहीं, 50 वर्ष पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाकर एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद पर कुठाराघात किया।

डॉ. मुखर्जी अपनी मानवीय संवेदनाओं और सेवाभाव के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। वर्ष 1943 में जब बंगाल भीषण अकाल की त्रासदी से जूझ रहा था, तब उन्होंने पीड़ितों की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि लोगों को भोजन मिल सके, जिसके लिए कई कैंटीन और रिलीफ सेंटर शुरू किए गए। एक ओर वे लोगों की पीड़ा से बहुत व्यथित थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत की असंवेदनशीलता से अत्यंत आक्रोशित भी थे। उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए पंचाशेर मन्वंतर नाम की एक किताब भी लिखी। 1942 में जब मेदिनीपुर में भीषण चक्रवात आया, तब उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का नेतृत्व किया।

कोलकाता के एक कॉलेज में युवाओं को संबोधित करते हुए डॉ. मुखर्जी ने उनसे आग्रह किया था, “आप जो भी कार्य करें, उसे पूरी गंभीरता, लगन और ईमानदारी से करें। किसी भी काम को कभी अधूरा न छोड़ें। तब तक स्वयं को संतुष्ट न मानें, जब तक आपने उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान न दे दिया हो।” आज हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम प्रतिदिन उस भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करें, जिसकी उन्होंने परिकल्पना की थी। एक ऐसा भारत जो सशक्त हो, एकजुट हो, आत्मविश्वास से भरपूर और संवेदनशील हो। देश के युवाओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बढ़-चढ़कर भागीदारी करेंगे और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाएंगे। ■

जिन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा को बनाया जीवन का ध्येय

कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका योगदान किसी एक कालखंड या एक भू-भाग तक सीमित नहीं रहता। प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथन ऐसे ही महान वैज्ञानिक और मां भारती के सपूत थे। उन्होंने विज्ञान को जनसेवा का माध्यम और खाद्य सुरक्षा को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उन्होंने वो चेतना जागृत की, जो सदियों तक भारत की नीति और प्राथमिकताओं को देती रहेगी दिशा...

■ जन्म : 7 अगस्त 1925 ■ मृत्यु : 28 सितंबर 2023

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। इस दौरान देश भोजन की कमी से जूझ रहा था। इस हालात ने एक युवक को झकझोर कर रख दिया। इस युवक ने तय किया कि देश में खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने कृषि की पढ़ाई शुरू की। यह युवक कोई और नहीं बल्कि एमएस स्वामीनाथन थे जिन्हें देश में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। ये वही स्वामीनाथन हैं जिन्होंने 1960-70 के दशक में गेहूं और धान की फसलों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के अपने ऐतिहासिक कार्य के जरिए लाखों लोगों को भुखमरी से बचा लिया। साथ ही भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाने वाले डॉ. स्वामीनाथन ने खेती में रसायन के बढ़ते प्रयोग और मोनोकल्चर खेती के खतरों से किसानों को लगातार जागरूक करते रहे।

7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन का पूरा नाम डॉ. मनकोम्बू साम्बशिवन स्वामीनाथन था। उन्होंने आर्थिक विकास के लिए रणनीतियों को विकसित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी आखिरी सांस तक वहां काम किया, जिसका लक्ष्य सीधे तौर पर गरीब किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करना था। उन्होंने वर्ष 1988 में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इतना ही नहीं, प्रोफेसर स्वामीनाथन ने भारत में कई प्रमुख पदों को नवीनता और रचनात्मकता के साथ संभाला। उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक 2004 में आई, जब उन्हें राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधिक आयु होने के बावजूद, स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग करने में सक्रिय रहे। उन्होंने अपने लेखन, सार्वजनिक भाषण के साथ कई मंच और सम्मेलनों में भाग लेकर ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा एवं सतत कृषि पर चर्चा में योगदान दिया। प्रोफेसर स्वामीनाथन ने कृषि विकास, अनुसंधान और नीति समर्थन के प्रति समर्पित संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया।

अनेकों सम्मान से सम्मानित स्वामीनाथन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन ने चुनौतीपूर्ण समय में भारत द्वारा कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। डॉ. स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की है। वह ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें मैं करीब से जानता था। मैंने हमेशा उनके दृष्टिकोण और विचारों की कद्र की है। ■

'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प से सशक्त होता नया भारत

15 अगस्त को जब देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तब हर भारतवासी के मन में एक ही संकल्प गूंज रहा है... आजादी के 100वें वर्ष में विकसित भारत की सिद्धि। स्वतंत्रता दिवस अब केवल एक आयोजन नहीं, यह उन महापुरुषों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया और सपनों के भारत के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। बीते 12 वर्ष में आजादी का यह जश्न विकास यात्रा के महोत्सव में बदल गया है। केंद्र सरकार ने एक मजबूत नींव पर भारत के नवनिर्माण को नई दिशा दी है, ताकि 2047 में शताब्दी वर्ष पर भारत विकासशील से विकसित राष्ट्रों की कतार में हो सके खड़ा...

लाल किले की प्राचीर से लहराता तिरंगा उन अमर सेनानियों, महिलाओं और पुरुषों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। यह संविधान सभा के उन सम्मानित सदस्यों को स्मरण करने का भी दिन है, जिन्होंने संविधान के माध्यम से हर भारतवासी को गर्व करने योग्य मूल अधिकार और शक्ति प्रदान की। यह आत्मनिरीक्षण का भी अवसर है। गौरवशाली अतीत को संजोने का, यह समझने का भी कि स्वाधीनता का सच्चा अर्थ क्या है, बीते आठ दशकों में देश किस दिशा में आगे बढ़ा है और आने वाले वर्षों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें क्या करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, "मेरी 'भारत की अवधारणा' न केवल सहिष्णुता पर आधारित है, बल्कि यह विचारों की विविधता

का प्रसन्नतापूर्वक समावेश करती है। इसका केंद्रीय सिद्धांत सत्य, शांति और अहिंसा से सृजित होता है। मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रतिबद्ध हूं जहां न्याय का चक्र-वर्ग, जाति या पंथ से प्रभावित हुए बिना हर नागरिक के लिए समान रूप से घूमे।" इसी सोच के साथ, समृद्ध भारत, सशक्त जनजीवन, व्यापक जनभागीदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के संकल्प को लेकर केंद्र सरकार दीर्घकालिक विजन के साथ आगे बढ़ रही है।

वर्ष 2014 में देश के जनमानस में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि कई नई परंपराओं का भी उदय हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आम बजट को एक माह पूर्व प्रस्तुत कर और 'गिव इट अप' जैसे जनआंदोलनों की नींव रखकर आजादी के जश्न के नए मानदंड स्थापित किए। 2014 के अपने पहले संबोधन में ही उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता और हर घर शौचालय का बीड़ा उठाया। इसे सच्चे अर्थों में जनआंदोलन बना दिया। इसी मंच से 'मेक इन इंडिया' का आह्वान हुआ, जिसे बाद में मैन्युफैक्चरिंग पर अधिक बल देते हुए 'मेक इन इंडिया 2.0' के रूप में विस्तार दिया गया। गरीबों को वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू हुई और जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिमूर्ति ने सीधे खाते में लाभ पहुंचाने वाले सुशासन का मार्ग प्रशस्त किया।

2015 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में ही स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की घोषणा हुई, आज सवा दो लाख से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने लगभग 11 करोड़ परिवारों को धुआं-मुक्त रसोई दी। आजादी के 70 वर्ष बाद भी अंधेरे में डूबे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई। 4 करोड़ से अधिक घर देकर प्रधानमंत्री के 'हाउसिंग फॉर ऑल' सपने को साकार किया जा रहा है। 2015 में निचले ग्रेड की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा हुई।

आजादी के सात दशक बाद भी मात्र तीन करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन थे और बड़ी आबादी दूषित जल से होने वाली बीमारियों से जूझ रही थी। इस चुनौती के समाधान के लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ही हर घर नल से जल पहुंचाने का लिया गया संकल्प आज साकार हो रहा है। भारत को 2047 तक ऊर्जा-संपन्न राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से 15 अगस्त 2021 को नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा भी इसी ऐतिहासिक प्राचीर से हुई। ऐसी योजनाओं की सूची बेहद लंबी है, जो लाल किले से घोषित होकर आज नए भारत के नवनिर्माण का आधारस्तंभ बन चुकी हैं।

यह वर्ष निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का है, तो संकल्पों से लैस इस भारत को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी भी हर नागरिक की है। सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था, "आइए हम अपने देश और देशवासियों में आस्था रखें और महान नेताओं के त्याग व बलिदान का सम्मान करते हुए उनके पथ पर आगे बढ़ें। आइए हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण के कार्य में 'राष्ट्र प्रथम' के मंत्र के साथ समर्पित करें।"

आइए, 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानें, बीते 12 वर्षों की उन 80 बड़ी उपलब्धियों को। जिन्होंने नए भारत को नई दिशा और नई गति दी है। साथ ही, अगले 20 वर्ष की विकास यात्रा का रखा है सशक्त आधार...

1 लोकतंत्र, सुशासन और ऐतिहासिक निर्णय

स्वतंत्रता दिवस का आयोजन अब केवल एक जश्न की तारीख नहीं, बल्कि बन गया है देश की विकास यात्रा का उत्सव और संकल्प...

1 जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए से मुक्ति, 5 अगस्त 2019, भारत के संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति, समृद्धि और शांति के नए युग की शुरुआत हुई।

2 अमृत महोत्सव

करीब **2.25** लाख

छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस श्रृंखला में औसतन हर घंटे 9-10 कार्यक्रम आयोजित हुए। यह अपने आप में एक अद्वितीय केस स्टडी है, जिसमें न केवल पूरी सरकार, बल्कि पूरे समाज का दृष्टिकोण अपनाया गया।

3

स्वप्रमाणन का दिया गया अधिकार। ग्रुप डी और सी की गैर-राजपत्रित नौकरी में साक्षात्कार समाप्त किया गया।

4

1 अगस्त 2019 को तीन तलाक कुप्रथा को खत्म करने का कानून लागू किया गया, तलाक की घटनाओं में

82%

से ज्यादा की कमी आई है।

5

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

- सितंबर 2023 में संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया जो विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- इस अधिनियम में लोकसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया।

6

25 दिसंबर, 2023 को भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत जून 2026 तक 75 लाख एफआईआर दर्ज, लगभग 60 लाख में चार्जशीट दायर, यौन अपराधों में चार्जशीट अनुपालन दर 2018 के मुकाबले लगभग दोगुनी हुई।

7

वर्ष 2017 में जीएसटी लागू कर 'एक राष्ट्र, एक कर' की व्यवस्था की गई। जीएसटी करदाताओं की संख्या 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 तक 1.65 करोड़ हो गई। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हो रहा। जीएसटी 2.0 ने उपभोक्ताओं की बचत का दायरा बढ़ाया।

8

ऐतिहासिक पहल और निर्णय

परीक्षा पे चर्चा

राष्ट्रीय वार मेमोरियल

प्रधानमंत्री संग्रहालय

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

वन नेशन वन राशन कार्ड

9

176 करोड़

लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए गए जून 2026 तक। सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाकर बिचौलियों की भूमिका समाप्त की गई।

2 अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन

अर्थव्यवस्था की प्रगति दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत। इस समावेशी विकास का लाभ सीधे आम नागरिकों को मिल रहा और जन-जन को मिला सुरक्षा का चक्र...

10

58.63 करोड़

से अधिक लोगों के बैंक एकाउंट जन धन योजना के तहत खोले गए 1 जुलाई 2026 तक, इन खातों में जमा हैं 3.08 लाख करोड़ रुपये।

11

24,162 करोड़

से ज्यादा हो गई है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (**UPI**) लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में, वित्त वर्ष 2016-17 में इसकी संख्या 2 करोड़ थी। यूपीआई की ग्लोबल पहुंच अब नौ देशों तक फैल गई है। डिजिटल भुगतान क्रांति आई और भारत आज दुनिया के सबसे बड़े रीयल-टाइम भुगतान तंत्रों में अग्रणी बन गया।

12

2.41

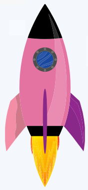

लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 1 जुलाई 2026 तक जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या करीब 350 थी। यूनिकॉर्न की संख्या 125 तक पहुंची है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से लगभग 25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।

13

5.5 लाख करोड़ रुपये

का मोबाइल निर्माण वर्ष 2026 में जबकि वर्ष 2014 में यह महज 18 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2026 में 2.6 लाख करोड़ रुपये का मोबाइल फोन निर्यात जबकि वर्ष 2014 में यह मात्र 1,600 करोड़ रुपये था।

14

1.91 लाख करोड़ रुपये

का बजट उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के लिए रखा गया है। दिसंबर 2025 तक 14 क्षेत्रों के उद्योगों के लिए 836 आवेदन की स्वीकृति मिली है। 31 दिसंबर 2025 तक 28,748 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।

15

57 करोड़

से अधिक लोन मुद्रा योजना के तहत उद्यमियों को बांटे गए हैं जिसमें 40.7 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

16

4.32

लाख करोड़ रुपये

की वसूली मार्च 2026 तक स्वीकृत समाधान योजनाओं के माध्यम से ऋणदाताओं ने की है।

17

701.4 अरब डॉलर

का विदेशी मुद्रा भंडार 16 जनवरी 2026 तक। वित्त वर्ष 2025-26 में भी 7.7% विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा।

18

सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 94.56 करोड़ आवेदकों को सामाजिक सुरक्षा कवर दिया।

3 विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष

विज्ञान-तकनीक और डिजिटल क्रांति ने विकास को अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाया है तो इस प्रगति ने दुनिया में भारत को दिलाई नई पहचान...

19

106.58 करोड़

हो गई है मार्च 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या। 'लास्ट-माइल' डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई।

20

950+ करोड़

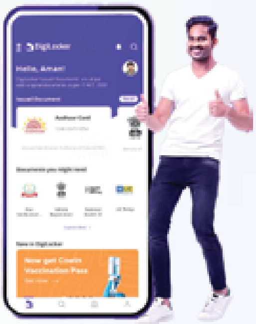

डिजिटल दस्तावेज डिजिलॉकर के जरिए जारी किए जा चुके हैं। अब एक क्लिक में जरूरी दस्तावेज, बिना कागजी झंझट- हर समय, हर जगह आपके साथ।

- पेंशनधारी के लिए जीवन प्रमाणन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई।

21

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने छोटे व्यापारियों को बड़े ई-कॉमर्स मंचों के समकक्ष डिजिटल पहुंच दी।

22

5+ लाख

से अधिक कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटर अप्रैल 2026 तक जबकि वर्ष 2014 में इसकी संख्या 83 हजार थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं की डिजिटल पहुंच और वितरण में सुधार।

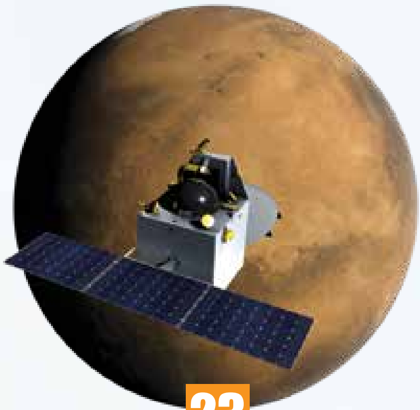

23

'मंगलयान' के जरिए भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचा। 24 सितंबर 2014 को इस यान ने मंगल की कक्षा में कदम रखा। इसी के साथ भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।

24

चंद्रयान-3 मिशन के तहत भारत 23 अगस्त, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला विश्व का पहला देश बना। चंद्रयान-3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा था, उसे 'शिव शक्ति' नाम दिया गया। हर वर्ष, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का निर्णय लिया गया।

25

आदित्य-एल1 मिशन के साथ भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपना पहला समर्पित अंतरिक्ष यान दो सितंबर 2023 को भेजा।

26

बड़ी कामयाबी : भारतीय गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (**ISS**) पर 18 दिनों का ऐतिहासिक वैज्ञानिक मिशन पूरा किया। इसके साथ ही 'एक्सिओम-04' मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस मिशन को 25 जून 2025 को स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया था।

27

जुलाई 2025 में भारत-अमेरिका सहयोग से **NISAR** उपग्रह का सफल प्रक्षेपण हुआ, जो विश्व का सबसे उन्नत पृथ्वी-अवलोकन रडार उपग्रह है।

28

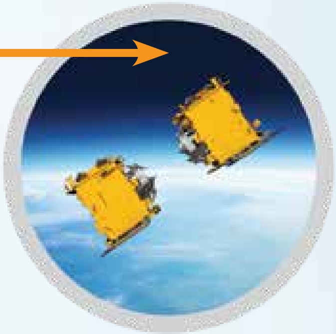

स्पाडेक्स मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना।

29

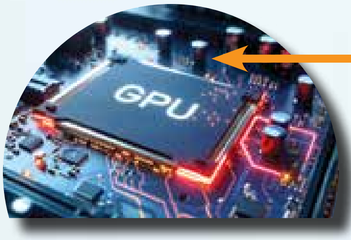

38,000

जीपीयू से अधिक हो गई देश की कंप्यूटिंग क्षमता राष्ट्रीय एआई मिशन के तहत, इसमें 20,000 जीपीयू और जोड़े जा रहे हैं। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुलभ और किफायती होगी।

30

- 5 सेमीकंडक्टर संयंत्रों के दिसंबर, 2026 तक चालू होने की उम्मीद, अभी तक 3 में कॉमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है, भारत ने किया सेमीकंडक्टर के नए युग में प्रवेश।
- 12 सेमीकंडक्टर इकाइयां देश भर में निर्माणाधीन, 24 डीप-टेक चिप डिजाइन स्टार्टअप शुरू, 70 हजार से अधिक युवा चिप डिजाइन में प्रशिक्षित।

4 रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा

रक्षा-सुरक्षा के नए युग में भारत आत्मनिर्भरता की नई पटकथा लिख रहा है। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, भारत की कड़ी कार्रवाई बन गई है नई नीति...

31

स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान

- स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान को फरवरी 2019 में अंतिम परिचालन मंजूरी मिली। भारतीय वायु सेना द्वारा 83 विमानों की खरीद को स्वीकृति।

32

रक्षा बजट

- लगभग 8 लाख करोड़ रुपये (2026-27)
- 2013-14 की तुलना में 3 गुना की वृद्धि।

रक्षा निर्यात

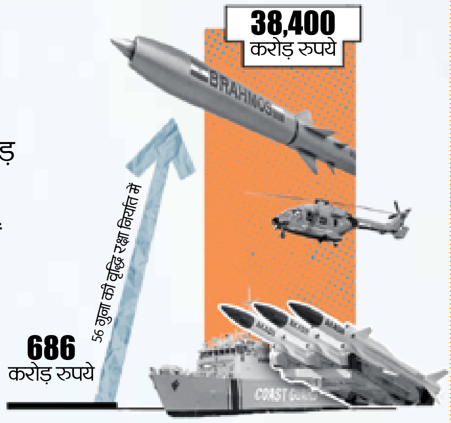

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात

भारतीय रक्षा उत्पाद 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहा। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका।

33

- 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए सीमा पार आतंकी ढांचों के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की गई।

34

2025 में ऑपरेशन सिंदूर

- 9 आतंकी कैंप नष्ट, 100 से अधिक आतंकी ढेर।
- 11 सैन्य ठिकानों पर सटीक प्रहार।
- 20% पाक वायु सेना ढांचे को नुकसान।

35

आईएनएस विक्रांत

- आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसका निर्माण 76% स्वदेशी सामग्री से किया गया।
- 2 सितंबर 2022 को कमीशन होने वाला यह पोत लगभग 30,000 टन स्टील से निर्मित।

2,200
कम्पार्टमेंट वाला एक तैरता हुआ शहर।

36

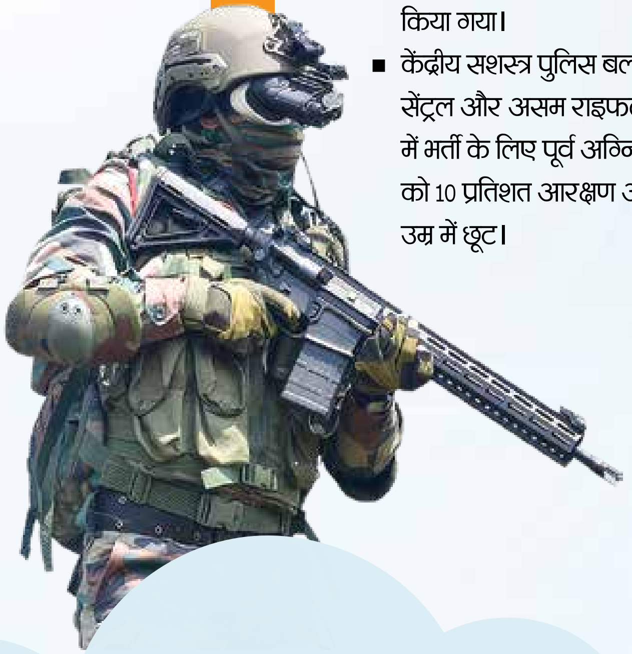

अग्निपथ योजना

- **जून 2022 में शुरू की** गई अग्निपथ योजना के तहत, फरवरी 2025 तक करीब 1.5 लाख अग्निवीरों को शामिल किया गया।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सेंट्रल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण और उम्र में छूट।

37

नक्सलवाद

- अप्रैल 2026 में देश को नक्सलवाद से मिली मुक्ति। लाल कॉरिडोर में अब विकास की तेज रफ्तार।

5 स्वास्थ्य और कल्याण

विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो या स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना, भारत सरकार ने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इससे स्वास्थ्य सेवा में पहुंच हुई आसान...

38

44 करोड़

से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) के तहत, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है निःशुल्क इलाज, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का होता है स्वास्थ्य बीमा।

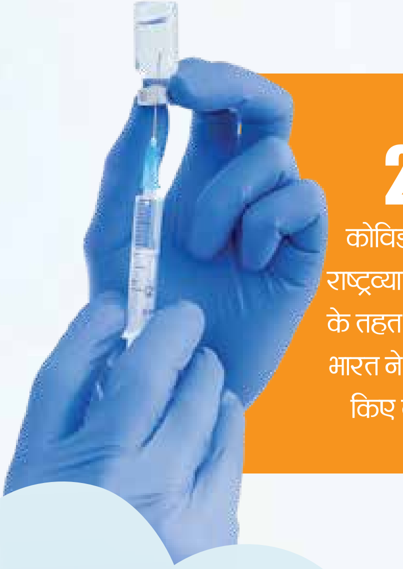

39

220 करोड़

कोविड-19 वैक्सीन की डोज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत दी गई। 30 करोड़ टीके भारत ने विश्व स्तर पर वितरित किए कोविड-19 के दौरान।

40

19,200

जन औषधि केंद्र की संख्या, ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 90% तक सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं यहां मिलती हैं। सर्जिकल उपकरण और स्वास्थ्य संबंधी उत्पाद (जैसे मात्र 1 रुपये में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन) भी मिलते हैं।

41

स्वच्छ भारत मिशन

12.11 करोड़

से ज्यादा घरों में शौचालय बनाए गए, जिससे ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर अब 100% हो गई है।

42

93.51 करोड़

से अधिक आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाए गए। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार होने से मरीज और चिकित्सक दोनों को हुई आसानी।

43

1.28 लाख से अधिक एमबीबीएस सीट 2026 में जबकि 2014 में यह संख्या 51 हजार थी। इसी अवधि में मेडिकल पीजी सीट की संख्या 31 हजार से बढ़कर 85 हजार से अधिक हुई। मेडिकल कॉलेज की संख्या 842 से 2,100 से अधिक हुई।

6 बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी

भारत में अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट न अटकते हैं, न लटकते हैं और न भटकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 12 वर्ष में 6 गुना हुआ तो कई इंफ्रा प्रोजेक्ट ने दुनिया में बनाई अलग पहचान, बढ़ी शान और जीवन हुआ आसान...

44

- 1,155 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क देश के 26 शहरों में फैला, बदला यात्रा का तौर तरीका।
- 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम से जुड़े 663 उड़ान (**UDAN**) मार्गों पर फ्लाइट चलाई गई।
- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क तैयार हुआ, उड़ान में आम लोगों को मिला सस्ता हवाई सफर।

45

- 164 वंदे भारत ट्रेन से रेल यात्रा को मिली नई गति, सुगम और तेज हुआ सफर।
- 4 करोड़ लोगों ने वित्त वर्ष 2025-26 में की वंदे भारत से यात्रा। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत फरवरी, 2019 में नई दिल्ली-वाराणसी के बीच शुरू हुई थी।

46

- 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की **PRAGATI** प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई समीक्षा।

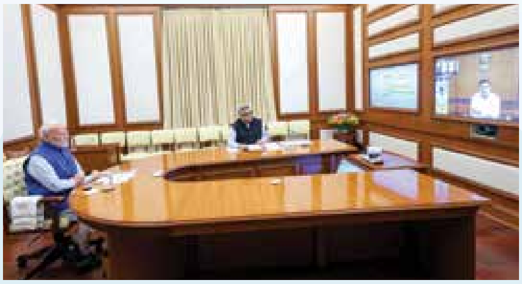

47

- 4+ करोड़ मकान लाभार्थियों को पीएम आवास योजना में सौंपे गए, अपने घर का सपना साकार।
- 74% घर या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई भावना पैदा हुई।

48

34,800

किलोमीटर कवर करने के लिए 5.35 लाख अनुमानित व्यय के साथ भारतमाला परियोजना चरण एक को मंजूरी दी गई।

- 26,425 किलोमीटर लंबाई वाली परियोजनाएं आवंटित, 22,223 किलोमीटर का निर्माण पूरा। देश में नियंत्रित हाईस्पीड कॉरिडोर की लंबाई 2014 में 93 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 3,644 किमी हुई।

49

- अटल टनल जैसी रणनीतिक और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने वाली सुरंगों के निर्माण से सामरिक और नागरिक कनेक्टिविटी दोनों मजबूत हुई।
- 9.02 किमी लंबी है अटल टनल, रोहतांग दर्रे को बाईपास करते हुए अत्यधिक ऊंचाई वाला मार्ग प्रदान करती है।
- 12 किमी लंबी सोनमर्ग सुरंग, समुद्र तल से 8,650 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई है।

7 कृषि और ग्रामीण विकास

कृषि और ग्रामीण विकास देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के मुख्य आधार हैं। सरकार खेती को आधुनिक बनाने, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर दे रही है जोर...

50
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

4.46+ लाख करोड़ रुपये

2019 में योजना की शुरुआत से अब तक वितरित किए गए।

- योजना के तहत 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय मदद मिल रही है। इनमें से 2.18 करोड़ महिला किसान हैं।

51
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

4 करोड़ से अधिक किसान पीएम फसल बीमा योजना से लाभान्वित।

- करीब 2 लाख करोड़ रुपये के दावों का भुगतान 2016 से लेकर 2025 तक किया गया।

52
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के तहत, 2025-26 में 97.53 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए और 92.87 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया।
- संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए 2015 से अब तक करीब 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।

53
कृषि उपज के निर्यात

- 51.9 अरब डॉलर था 2024-25 में कृषि और उससे जुड़ी कमोडिटीज उत्पादों का कुल निर्यात।
- कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो गई है।

54
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- 4.06 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बीते 12 वर्ष से भी कम समय में बनीं, 99% गांव पक्की सड़क से कनेक्ट।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III को मार्च 2025 से आगे बढ़ाकर मार्च 2028 तक जारी रखने को मंजूरी।

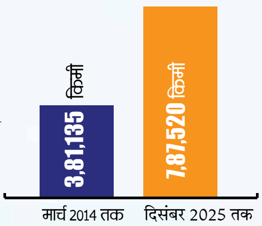

8 शिक्षा और कौशल विकास

देश में तीन दशक बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई तो उच्च शिक्षा का इंफ्रा भी बढ़ा। कौशल विकास ने बढ़ाए युवाओं के लिए अवसर तो अब युवा बन रहे हैं विकसित भारत के सारथी...

55

तीन दशक बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**NEP** 2020) मिली। शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक, लचीला और कौशल-आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।

170 **विश्वविद्यालयों ने अपनाया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क**

2,469 **संस्थान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़े**

32 **करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट आईडी जारी**

56

6+ करोड़ अभ्यर्थी कौशल विकास पहल के माध्यम से प्रशिक्षित, कुशल भारत मिशन के पीएमकेवीवाई, जेएसएस, एनएपीएस और सीटीएस व अन्य माध्यम से किया गया प्रशिक्षित।

15,000 के करीब पहुंची आईटीआई की संख्या, उसमें पढ़ रहे हैं करीब 15 लाख छात्र, युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण देकर बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर।

57

- 3.66 लाख से अधिक ई-कंटेंट संसाधन दीक्षा में 135 भाषाओं में उपलब्ध है। स्वयंप्रभा, पीएम ई-विद्या, रेडियो, डिजिटल कंटेंट सहित अन्य डिजिटल शिक्षा मंचों ने दूरदराज के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री पहुंचाई।

6.1+ **करोड़ नामांकन डिजिटल स्वयं प्लेटफॉर्म पर हुए**

18,580 पाठ्यक्रम उपलब्ध

58

- 23 हुई एम्स की संख्या जो 2014 में सिर्फ 7 थे, एमबीबीएस की सीटें 1.29 लाख तो मेडिकल की पीजी सीटें करीब 86 हजार पहुंची, चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ाया गया।
- 23 **IIT**, 22 **IIM**, 25 **IIIT** सहित देश भर में खुले संस्थानों और परिसरों की स्थापना कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- आर्थिक रूप से कमजोर सर्वणों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।

59

13,092 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 21 घटकों के साथ **PM** श्री स्कूल योजना में अपग्रेड करने के लिए चयन किया गया।

499 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अब 1.56 लाख छात्रों का नामांकन, वहीं अटल टिंकरिंग लैब से जुड़े 1 करोड़ छात्र नवाचार से जुड़ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं।

9 महिला सशक्तीकरण

देश की आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना देश को विकसित करने की कल्पना मुश्किल है। यही वजह है कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकताओं में है सर्वोपरि...

60

- घटते बाल लिंग अनुपात और व्यापक लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।

- राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया।

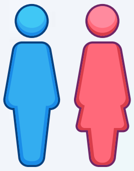

62

मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं

68% मुद्रा योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं। इससे आसान ऋण और व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिली।

- **घर से कारोबार तक** : मुद्रा योजना महिलाओं को आत्मविश्वास दे रही है। इस योजना के 11 साल पूरे।
- **स्टैंड-अप इंडिया** : महिलाएं 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिसे चुकाने के लिए 7 वर्ष तक का समय मिलता है।
- स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से, महिलाओं को आवेदन पर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण से जुड़ने का अवसर मिलता है।

61

जल जीवन मिशन

12.65+ करोड़

अतिरिक्त नल कनेक्शन ग्रामीण परिवारों को मिशन की शुरुआत 15 अगस्त, 2019 से 10 जुलाई 2026 तक दिए गए।

- 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास ही थे मिशन की शुरुआत के समय नल कनेक्शन।

15.88+ करोड़

परिवारों को अब मिलने लगा नल से जल, 19.35+ करोड़ हैं देश में ग्रामीण परिवार।

- स्वतंत्रता दिवस पर घोषित इस मिशन की वजह से महिलाओं का पानी लाने में लगने वाले समय की बचत हुई, आर्थिक गतिविधियों में उस समय का इस्तेमाल कर सशक्त हो रही है नारी।

63

सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन और लड़ाकू भूमिकाओं में नियुक्ति

- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश में खासी प्रगति हुई है, मई 2025 में 17 महिला कैडेट और नवंबर 2025 में 15 महिला कैडेट स्नातक हुईं।
- महिला अधिकारी अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, फाइटर पायलट और प्रमुख इकाइयों की कमांडरों सहित वरिष्ठ नेतृत्व और परिचालन कमान की भूमिकाएं निभा रही हैं।
- लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती साल 2015 में प्रायोगिक आधार पर शुरू। 2022 में स्थायी योजना के तौर पर उसे दिया गया औपचारिक रूप।

सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़कर लगभग **11,000** तक पहुंच गई है

64 पीएम उज्ज्वला योजना

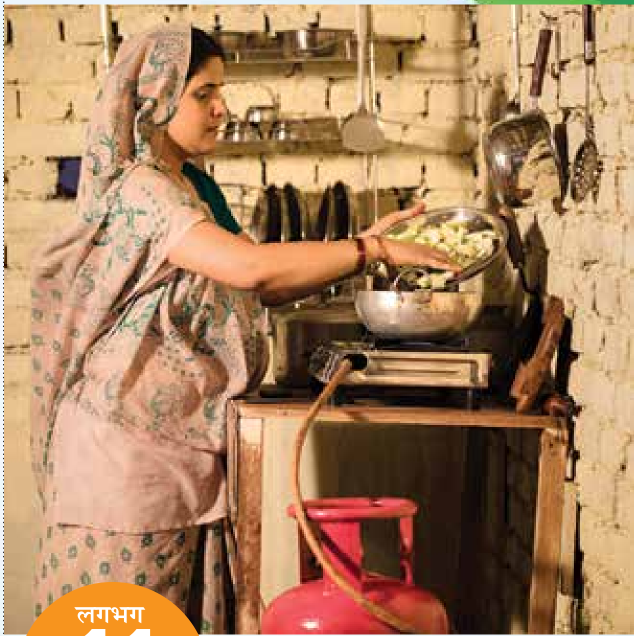

लगभग **11 करोड़** एलपीजी कनेक्शन दिए गए। रसोई घरों को धुआं-मुक्त बनाया गया।

- महिलाओं के प्रतिदिन 2 से 3 घंटे बच जाते हैं, जो पहले उन्हें चूल्हा जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने में लगते थे।
- देश में एलपीजी की पहुंच 55.9 प्रतिशत (अप्रैल 2014) से बढ़कर 107.2 प्रतिशत (अप्रैल 2026) हो गई।
- उपभोक्ताओं की संख्या 14.51 करोड़ (अप्रैल 2014) से बढ़कर 33.39 करोड़ (अप्रैल 2026) हो गई और खपत दोगुनी हो गई।

10 खेल

खेल-खेल में खेलो इंडिया ने न सिर्फ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया बल्कि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने का काम भी हुआ। अब ओलंपिक हो या पैरालंपिक, क्रिकेट हो या कुश्ती, पुरुष हों या नारी शक्ति हर तरफ लहरा रहा भारत का परचम...

65

- **30,750+** एथलीटों को खेलो इंडिया से सहायता, मणिपुर के इंफाल में 2018 में बना देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने का तैयार किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर।
- 4.5 लाख से अधिक स्कूल फिट इंडिया स्कूल फ्लैग से सम्मानित, करीब 24 करोड़ लोग फिट इंडिया रन सहित अन्य कार्यक्रम में हुए शामिल।

66

- 6 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीते। 1952 से 2012 यानी 60 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में 20 पदक जीते, 2016-2024 के बीच 15 पदक जीते।

- **107** पदक भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में जीतकर रिकॉर्ड बनाया। खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की बढ़ती पदक संख्या ने देश को खेल जगत में नई पहचान दी।

67

2025 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जबकि महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया

भारतीय टीम, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 और 2026 में जीतने के साथ तीन बार जीती, महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने भी विश्व कप जीतकर खेल जगत में इतिहास रचा।

11 विदेश नीति और वैश्विक पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का न सिर्फ मान वैश्विक स्तर पर बढ़ा है बल्कि भारत विकसित होते देशों की भी बन रहा है आवाज...

68

जी-20

का 2023 में भारत की अध्यक्षता में सफल आयोजन

- भारत ने 'ग्लोबल साउथ' की आवाज बनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीतिक साख मजबूत की।
- 100% जी-20 नेताओं की नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (एनडीएलडी) पर सहमति।

69

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

- 175 देशों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संयुक्त राष्ट्र में दिया समर्थन।
- 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित रेड रोड से किया।
- 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' पर 2026 में दुनिया के **2,500** से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम हुए।

70

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

- **125** सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक मंच के रूप में उभरा।
- भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी21 जलवायु सम्मेलन के दौरान इस गठबंधन की शुरुआत की।
- आईएसए का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में **1,000** अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है।

71

कोविड काल में वैक्सीन मैत्री

वैक्सीन मैत्री के तहत 99 देशों को 30 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी गई।

73

यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाकर **'इंडिया फर्स्ट'** के दृष्टिकोण को मजबूती से स्थापित किया।

72

पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट

- पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के जरिए क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को मिली नई दिशा।
- यह नीति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यामां, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ मजबूत भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता देती है।
- एशियाई और पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान की गई।

12 पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण

भारत ने विश्व को LiFE और अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का मंत्र दिया तो देश में वन क्षेत्र बढ़ाने और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले रामसर साइट, वन क्षेत्र और विलुप्त चीता की संख्या बढ़ी। वहीं सतत विकास लक्ष्य हुए समय से पहले हासिल...

74

53 हुई भारत में चीतों की संख्या, इसमें 33 का जन्म भारत में हुआ है, यह लुप्त हो चुकी प्रजाति की वापसी का प्रतीक है।

- 1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित किया गया था, सितंबर 2022 में विश्व में पहली बार किसी विशाल मांसाहारी जानवर का अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण कर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे।

75

- **283.46** गीगावाट हुई 31 मार्च, 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, इसमें 274.68 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।
- भारत, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है।

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन

- 8.62 लाख टन/साल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को मंजूरी, स्टील सेक्टर के लिए 7 और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 5 पायलट प्रोजेक्ट शुरू।
- मिशन से 8 लाख करोड़ रु. निवेश आने, छह लाख रोजगार सृजन और जीवाश्म ईंधन के आयात में सालाना 1 लाख करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद।

76

- **43,031** करोड़ रुपये की 524 परियोजनाओं को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नदी गंगा सहित अन्य नदियों की स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए मंजूरी दी गई जिसमें 363 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- 100 हुई भारत में रामसर साइट की संख्या, 2014 में महज 26 थी।
- 18 हुई ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तटों की संख्या, 2020 में पहली बार 8 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था।

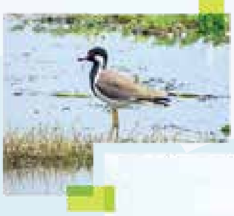

77

- मिशन LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली को वैश्विक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया गया। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की मौजूदगी में 2022 में लॉन्च किया गया।

13 संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत

भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत विश्व की प्राचीनतम जीवंत धरोहर है। यह केवल परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शाश्वत कला है। सत्य, अहिंसा और 'वसुधैव कुटुंबकम्' के दर्शन से पोषित यह विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान और वैश्विक गौरव का है आधार...

78

- **2025** में आयोजित प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
- इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन गया।
- यह संख्या उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण अमेरिका की कुल आबादी से भी अधिक।

79

- 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों भारतीयों की आस्था को नया आयाम दिया।
- अयोध्या श्री राम मंदिर में बीते 4 साल में **16** करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

80

- 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन।
- उज्जैन महाकाल लोक कॉरिडोर, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, सोमनाथ का पुनरोद्धार, डेराबाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

सेमीकॉन 2.0 और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी

भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जैसी योजनाओं को दी है मंजूरी...

कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

निर्णय : सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी।

प्रभाव : आर्थिक विकास को गति मिलेगी, आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत होगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगी।

- सेमीकॉन 2.0 के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को छह प्रमुख स्तंभों के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। इस मिशन के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान है।

निर्णय : उत्तर प्रदेश में वरुणा नदी तट के किनारे 6/4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, रैंप और लूप के निर्माण को हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत 10,998.32 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी।

प्रभाव : यह परियोजना वाराणसी डी-कंजेशन योजना का एक प्रमुख हिस्सा है जो एनएच-31 और काशी रेलवे स्टेशन के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट पूरा होने पर एनएच-31 से काशी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा के समय में 50% की कमी आएगी।

- प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। छह प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। कॉरिडोर की लंबाई: 43.218 किमी।

निर्णय : मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी।

प्रभाव : योजना की अवधि 5 वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2030-31 तक है। इसके लिए 62,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे देश में मोबाइल फोन के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और उत्पादन लगभग 39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।

- इस योजना से 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने से आर्थिक विकास, रोजगार और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

निर्णय : ओडिशा और झारखंड के चार जिलों के लिए दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

प्रभाव : इन परियोजनाओं से रेल संचालन अधिक सुगम होगा। रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी। मौजूदा रेल नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की वृद्धि होगी। परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 3,907 करोड़ रुपये है। ये 2030-31 तक पूरी हो जाएंगी।

दो मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजना

- पारादीप-हरिदासपुर रेलखंड का दोहरीकरण।
- राजखरसावां-डांगोआपोसी रेलखंड पर चौथी रेल लाइन का निर्माण।

निर्णय : आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से यूरिया-2026 (एनआईपीयू-2026) के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी।

प्रभाव : यह नीति देश में गैस आधारित यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए यूरिया सेक्टर में नए निवेश को बढ़ावा देगी। इससे आत्मनिर्भरता का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। एनआईपीयू-2026 नीति के तहत करीब 8 से 9 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे।

निर्णय : वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच गंगा नदी के तट पर कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले एक लिंक कॉरिडोर के विकास को मंजूरी।

प्रभाव : 46.039 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में छह लेन का एलिवेटेड मेन कैरिजवे, एक केबल-स्टे ब्रिज, एक एक्स्ट्रा डोज्ड फुट ओवर ब्रिज-कम-मेजर ब्रिज, लूप, रैंप, लिंक रोड और सर्विस रोड शामिल हैं। परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत कुल 14,447.64 करोड़ रुपये की पूंजी लागत पर कार्यान्वित की जाएगी। ▪

दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता भारत

राजस्थान की धरती अनगिनत वीरों के शौर्य की साक्षी रही है। यहां के कण-कण ने स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की सीख दी है। व्यक्ति का स्वाभिमान हो या फिर देश का, वो तभी ऊंचा रह सकता है जब वो आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम की इसी कड़ी में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन...

चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है। आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। राजस्थान के बालोतरा में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ही, जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन भी किया गया है। यह मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।

> "आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। आज राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो रहा है। जयपुर मेट्रो फेज-2 की आधारशिला और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन राजस्थान के विकास को और गति देंगे।
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

संशोधित उड़ान योजना लॉन्च

- जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना लॉन्च। क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रु. आवंटन। इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन-आधारित विकास को गति देना है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन

₹480 करोड़ की लागत से विकसित जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन।

23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम।

- आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित, यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
- राजस्थान की शाही विरासत से प्रेरित वास्तुकला के साथ इस टर्मिनल में मेहराब और झरोखों जैसे पारंपरिक तत्व समकालीन डिजाइन के साथ खूबसूरती से शामिल।
- ऊर्जा-कुशल प्रणालियों, जल संरक्षण उपायों और हरित भवन निर्माण पद्धतियों जैसी विशेषताएं टर्मिनल के डिजाइन के अभिन्न अंग हैं।

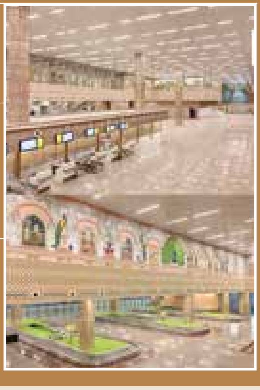

आधारशिला और उद्घाटन

- बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन।
- ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी।
- बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित।

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग **54,000** युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित।

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला

₹13,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखी गई।

लगभग **₹900** करोड़ की लागत से निर्मित चूरू-सादुलपुर (58 किमी) और चूरू-रतनगढ़ (46 किमी) रेल दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित।

- एसजेवीएन लिमिटेड की 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित।
- एनएचपीसी के 300 मेगावाट के करणीसर बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित।
- राजस्थान आरईजेड के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली ट्रांसमिशन प्रणाली की आधारशिला।

1,900 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन।

कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं, अगर उनके पीछे की नियत साफ हो। राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में विकास के और भी नए आयाम छूने हैं। हम साथ मिलकर राजस्थान के नए भविष्य का निर्माण करेंगे।

नेक्स्ट जेन टेक क्रांति...

भारत में सेमीकंडक्टर का नया युग

भारत जो ठान लेता है, वो करके दिखाता है। करीब 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर का हब बनाएंगे। राष्ट्र मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि सेमीकंडक्टर इकाइयों पर तेजी से काम शुरू किया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) सुविधा का उद्घाटन किया। सेमीकंडक्टर की इस तीसरी इकाई में अब चिप पैकेजिंग का शुरू हुआ कमर्शियल प्रोडक्शन...

भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर की प्रगति से आज सभी उत्साहित हैं। देश-दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ। यह पिछले एक दशक में, भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। गुजरात के साणंद में ओएसएटी सुविधा के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास, कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है। भारत केवल मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएगा

> *आने वाले समय में AI आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए, भारत के युवाओं को अब ये अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं - आईडिया आपका, साथ मेरा।*
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

₹7,500 करोड़ से अधिक के कुल निवेश से विकसित संयंत्र

- गुजरात के साणंद में स्थित ओएसएटी संयंत्र से हर साल 20 करोड़ चिप निकलेंगी।
- भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू।
- वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम।
- यह परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली चार परियोजनाओं में से एक।

5 अरब सेमीकंडक्टर चिप तक होगी इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता

- पूर्ण क्षमता के साथ संचालन के बाद, इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप तक होगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहायक।
- संयंत्र ऑटोमोटिव, औद्योगिक, दूरसंचार, 5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करेगा।

दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल निर्माता

2014 के पहले भारत अपनी जरूरत का अधिकांश स्मार्ट फोन विदेश से मंगाता था। आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफेक्चरर और मोबाइल निर्यातक है।

आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले, लगभग 7 गुना और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ा। यह सेक्टर लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री बन गया है। इससे 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।

12 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माणाधीन

वर्तमान में भारत में 12 सेमीकंडक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं, 24 डीप-टेक चिप डिजाइन स्टार्टअप शुरू हुए हैं, 70 हजार से अधिक युवाओं को चिप डिजाइन में प्रशिक्षित किया गया है। 315 विश्वविद्यालय अब सेमीकंडक्टर डिजाइन से संबंधित कोर्स करा रही हैं। ढोलेरा में बन रही भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब तेजी से आगे बढ़ रही है।

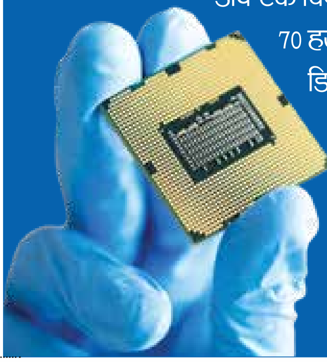

बल्कि चिप का निर्माण भी करेगा, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है।

जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है, तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। जब आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर और एआई रेवोल्यूशन का दौर भी अनगिनत नए अवसर लेकर आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर, स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक, अनेक अवसर हैं। ▪

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पीएम तकाइची सनाए की भारत यात्रा

प्रगति और रणनीतिक तालमेल का नया अध्याय

भारत-जापान के अटूट विश्वास और विशेष रणनीतिक साझेदारी में जुलाई 2026 में एक नया अध्याय जुड़ा, जब जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए अपने पहले आधिकारिक दौरे पर 1-3 जुलाई तक भारत में रहीं। 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों वैश्विक शक्तियों के बीच रक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित सुरक्षित, भरोसेमंद और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इकोसिस्टम बनाने पर बनी सहमति...

भारत और जापान का आपसी सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे भारत-प्रशांत क्षेत्र की खुशहाली और विकास के लिए भी जरूरी है। तेजी से बदलते वैश्विक माहौल में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-जापान साझेदारी के रणनीतिक महत्व को समझा। आपसी संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, दोनों नेता रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित आर्थिक साझेदारी में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए ने कहा कि दुनिया के अग्रणी लोकतंत्र और प्रमुख

ऑटोमोटिव और मेक इन इंडिया

- **सुजुकी का ग्लोबल हब बना भारत:** दुनिया भर में सुजुकी की दो-तिहाई कारें अब भारत में बन रही हैं, जिन्हें 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
- **खरखौदा में नया प्लांट:** हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के अत्याधुनिक नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है।
- **सफलता का मंत्र:** जब जापान की एक्सपर्टीज और इंवेस्टमेंट, भारत की स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है, तो इसका फायदा पूरी दुनिया को होता है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी

- **ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा:** 'भारत-जापान सहकारी बायोगैस विकास पहल', भारत में 1,000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र लगाने का लक्ष्य है।
- **2027 तक बुलेट ट्रेन:** जापानी पीएम ने भरोसा दिया कि भारत में वर्ष 2027 तक बुलेट ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए जापान हर जरूरी मदद करेगा।
- **कंज्यूमर देशों की मजबूत आवाज:** ऊर्जा की ज्यादा खपत करने वाले दोनों देश वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को और मजबूत करेंगे।
- **ऊर्जा परिवहन में सहयोग:** तेल और प्राकृतिक गैस के सुरक्षित समुद्री परिवहन के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे।
- **सुरक्षित एआई इकोसिस्टम:** भारत-प्रशांत क्षेत्र सहित पूरी दुनिया के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद एआई इकोसिस्टम बनाने पर जोर।
- **भारतीय एआई टैलेंट को मौका:** वर्ष 2030 तक भारत से 500 कुशल एआई पेशेवरों को जापान आमंत्रित करेगा।

पर्यटन और पीपल टू पीपल कनेक्ट: वर्ष 2025 में भारत-जापान के बीच यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 5.40 लाख के पार।

क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे

- **समृद्ध भारत-प्रशांत का विजन :** मजबूत और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाएंगे।
- **समुद्री सुरक्षा पर कड़ा रुख :** पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर मंथन। यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध।
- **अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान :** समुद्री विवादों का समाधान हर हाल में शांतिपूर्ण ढंग से और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में ही होना चाहिए।
- **उत्तर कोरिया पर चिंता :** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के तहत उसके पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग दोहराई गई।
- **UNSC में तत्काल सुधार :** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए अन्य G-4 देशों के साथ मिलकर काम करने का संकल्प, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार शामिल है।
- **सीटों के लिए आपसी समर्थन :** भारत और जापान ने वर्ष 2028-29 और 2033-34 में सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करने पर सहमति जताई।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

व्यापार और निवेश

- **10 ट्रिलियन येन का बड़ा लक्ष्य:** अगले एक दशक में जापान से भारत में निवेश को 10 ट्रिलियन येन के पार ले जाने का मजबूत संकल्प।
- **बंपर बिजनेस एग्रीमेंट:** पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच 100 से अधिक नए व्यापारिक समझौते हुए, जिससे भारत में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का जापानी निवेश आएगा।
- **निवेश के लिए फास्ट-ट्रैक सिस्टम:** 'भारत-जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप' के तहत फास्ट-ट्रैक व्यवस्था से निवेश के माहौल को और शानदार बनाया जाएगा।
- **रणनीतिक सप्लाई चेन:** सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस्ड मैटेरियल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन व्यवस्था को सुगम और मजबूत किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के रूप में उनका यह कर्तव्य है कि वे एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार दें, जो स्वतंत्र, खुली और कानून के शासन पर आधारित हो। दोनों प्रधानमंत्री ने अपने-अपने मंत्रियों को इस वर्ष के अंत तक टोक्यो में '2+2' मंत्रिस्तरीय बैठक के चौथे दौर का आयोजन करने का निर्देश दिया। दोनों नेताओं ने 'आर्थिक सुरक्षा पहल' के तहत हुई प्रगति की सराहना की, जिसमें इस वर्ष आयोजित पहला निजी क्षेत्र आर्थिक सुरक्षा संवाद और इस वार्ता का दूसरा दौर शामिल है। इसके साथ ही, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और फार्मा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रोजेक्ट-आधारित सहयोग को बढ़ाने के लिए 'आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत-जापान संयुक्त घोषणा' को भी मंजूरी दी गई। ■

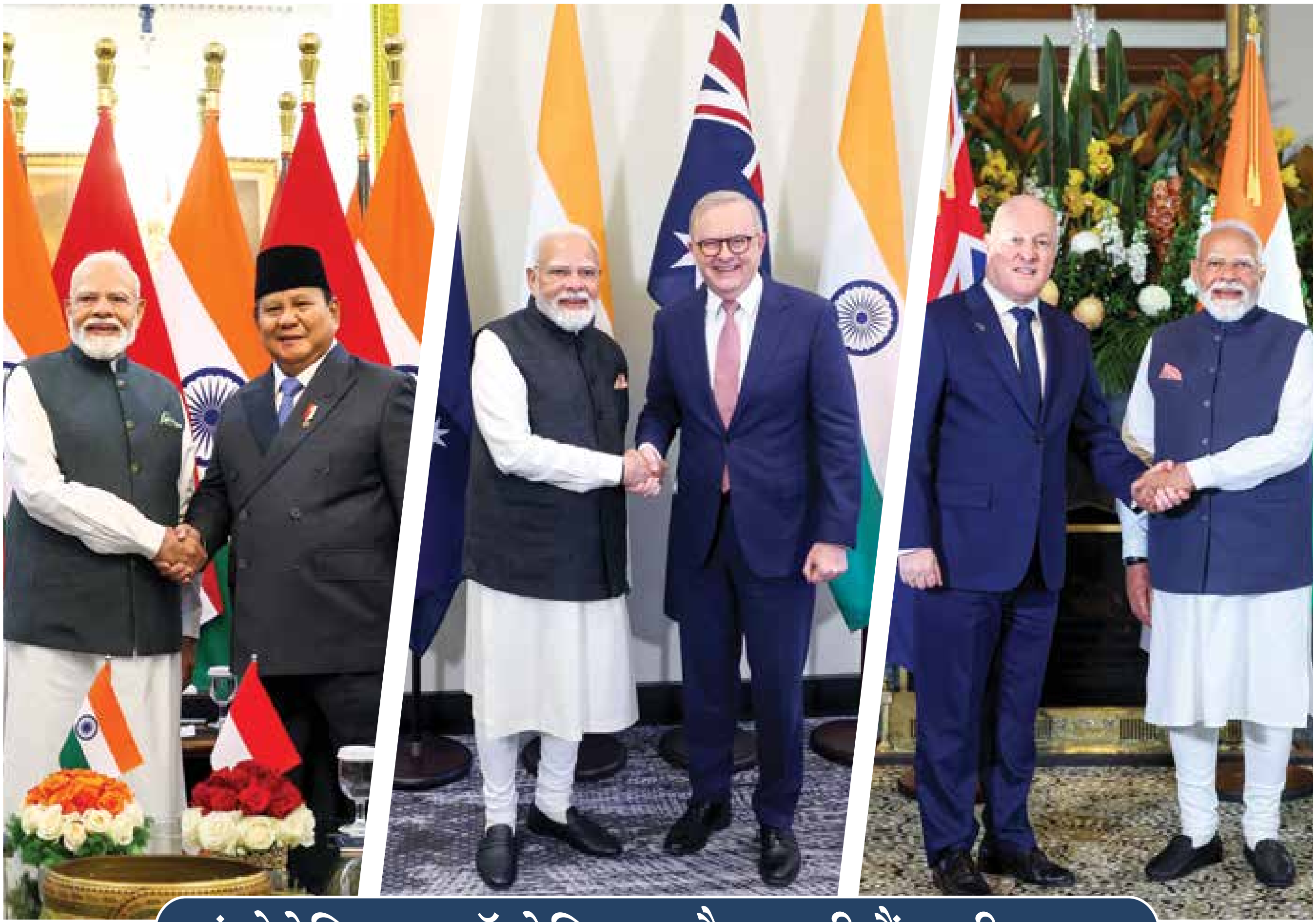

इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा

वैश्विक रिश्तों को नई उड़ान

इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा इन देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों की एक नई उड़ान है। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति एवं समुद्री विजन को और मजबूत करेगी। साथ ही, यह एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सपने को भी आगे बढ़ाएगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति सहित कई द्विपक्षीय व वैश्विक मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा और हुए दर्जनों समझौते...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से 11 जुलाई तक हुई इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा कई मायनों में बेहद खास रही। इस दौरान बदलते वैश्विक माहौल के बीच आपसी रिश्तों को मजबूत करने और भविष्य के कई अहम समझौतों पर खुलकर चर्चा हुई। इस दौरे ने न सिर्फ भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को रफ्तार दी है, बल्कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत के विजन को भी और मजबूत किया है।

इंडोनेशिया

महत्वपूर्ण समझौता और घोषणाएं

- ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग।
- वायु से वायु मिसाइल सहयोग समझौता।
- इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पं. क्राकाटाऊ स्टील के बीच समझौता।
- योग्याकार्ता के प्रंबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत करेगा सहायता।
- आईएफसी-आईओआर में इंडोनेशियाई संपर्क अधिकारी तैनात।
- "टैगोर-देवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक कूटनीति वर्ष" का स्मरणोत्सव मनाया जाएगा।
- सिंघासरी एसईजेड, इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु शाखा परिसर की स्थापना।

इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की जननी भारत, इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंधों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' तथा 'भिन्नेका तुंग्गल इका' (विविधता में एकता) के साझा आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि यही मूल्य दोनों देशों की साझेदारी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों की भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय सहयोग के लिए गंगा-महाकम विजन के आधार पर भारत-इंडोनेशिया संबंधों में एक नई शुरुआत का आह्वान किया।

इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

बिंतांग आदिपूर्ण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण प्रदान किया। यह सम्मान भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके नेतृत्व और असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

दोनों देशों की मित्रता में आधारस्तंभ हैं भारतीय प्रवासी

जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया की प्रगति और समृद्धि एवं दोनों देशों के बीच मित्रता में भारतीय प्रवासी एक आधारस्तंभ हैं। प्रवासी समुदाय से 'विकसित भारत 2047' और 'इंडोनेशिया एमास 2045' की साझा आकांक्षाओं को साकार करने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच दो हजार वर्ष से भी अधिक पुराने गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंध हैं। आज, इंडोनेशिया लगभग 1.50 लाख भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) और करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का घर है।

दोनों देशों के बीच इन विषयों पर हुई चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच जकार्ता के इस्ताना मर्देका में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। राजनीतिक जुड़ाव, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, व्यापार एवं निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, औषधि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, युवा आदान-प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रंबानन मंदिर परिसर में दर्शन किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रंबानन मंदिर परिसर में दर्शन किए। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंदिर में दर्शन के लिए उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने मंदिर परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण और जीर्णोद्धार परियोजना के शुभारंभ के उपलक्ष्य में एक पट्टिका का अनावरण किया। 9वीं शताब्दी में निर्मित, प्रंबानन मंदिर परिसर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है।

ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों का संयुक्त दृष्टिकोण

यूरेनियम और क्लीन एनर्जी: परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा समझौता हुआ है। अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे भारत को पर्यावरण अनुकूल (क्लीन) एनर्जी बनाने में मदद मिलेगी।

क्रिटिकल मिनरल्स: दोनों देश मिलकर 'क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर' बनाने पर काम करेंगे, ताकि जरूरी खनिजों की सप्लाई आसानी से हो सके।

रक्षा और सुरक्षा में सहयोग: दोनों देश मिलकर एक 'डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर' बनाएंगे। इसका मकसद दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप और डिफेंस कंपनियों को एक साथ लाना है।

शिक्षा और नॉलेज पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों के कैंपस अब भारत में खुल रहे हैं। इससे दोनों देशों के बीच पढ़ाई-लिखाई और ज्ञान का तालमेल और मजबूत होगा।

खेलों का आयोजन आने वाले सालों में दोनों देशों में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी की जाएगी।

बढ़ रहे व्यावसायिक अवसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 'ऑस्ट्रेलिया-भारत सीईओ फोरम' तथा 'इकोनॉमिक रोडमैप' बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के 200 से अधिक शीर्ष बिजनेस लीडर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि भारत की सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि, निरंतर प्रशासनिक सुधार, डिजिटल परिवर्तन और इनोवेशन का अनुकूल माहौल, ऑस्ट्रेलियाई कारोबारी भागीदारों के लिए व्यापार के नए एवं असीम अवसर पैदा कर रहा है।

साइबर सुरक्षा

ऑस्ट्रेलिया और भारत साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, साइबर अपराधों को रोकने और अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देश आपस में तकनीकी ज्ञान साझा करने, व्यापार एवं निवेश के अवसर बढ़ाने और कौशल विकास के लिए एक इनक्यूबेटर हब बनाने पर सहमत हुए हैं। साथ ही, वे इस सहयोग को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मजबूत द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करेंगे ताकि वैश्विक मंचों पर बेहतर तालमेल बन सके।

प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच सेतु

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की सराहना की। उन्होंने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए प्रवासी भारतीयों को दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु बताया।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

न्यूजीलैंड

'भारत-न्यूज़ीलैंड: एक सफल साझेदारी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा आयोजित 'भारत-न्यूज़ीलैंडः एक सफल साझेदारी' विषय पर आधारित एक विशेष भोज समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजनीति, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, खेल और कला जगत की कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता रिकॉर्ड समय में पूरा करने पर बात हुई। कहा गया कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों, युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर खुलेंगे और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

'किया ओरा मोदी' कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में 'किया ओरा मोदी' कार्यक्रम में न्यूज़ीलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सभा भले ही भारतीय प्रवासियों की हो, लेकिन वास्तव में यह भारत-न्यूज़ीलैंड की मित्रता, खेल संबंधों और आर्थिक साझेदारी का समारोह है।

निवेश और व्यावसायिक साझेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवसाय जगत को निवेश एवं व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने का आह्वान किया। इस बात पर जोर दिया कि भारत-न्यूज़ीलैंड आर्थिक साझेदारी समावेशी एवं सतत व्यापार का एक मॉडल बनने के साथ ही इनोवेशन एवं समृद्धि का एक मंच बन सकती है।

2030 तक का रोडमैप

40 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड की आधिकारिक यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया। अगले चार सालों के लिए संयुक्त कार्रवाई के रूप में उन्होंने 'भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी: 2030 का रोडमैप' को अनुमोदित किया। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में रक्षा और सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, व्यापार और आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, शिक्षा, अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा आपदा प्रबंधन, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में साथ मिल कर काम करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

खेल और विज्ञान

भारतीय महिला क्रिकेट

स्वर्णिम भविष्य का दमदार उद्घोष

लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर तब इतिहास रचा गया जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इस ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए पहले महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार जीत हासिल की। यह कामयाबी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर मिली जीत नहीं है बल्कि यह भारतीय महिला क्रिकेट में एक आत्मविश्वास और मजबूत नए दौर की शुरुआत का है प्रतीक...

क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स पर खेले गए पहले महिला टेस्ट में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया। यह जीत लॉर्ड्स में महिला टेस्ट जीतने वाली पहली टीम बनने का गौरव लेकर आई। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के स्वर्णिम भविष्य की दमदार घोषणा है। 21 जुलाई से 23 जुलाई 1884 के बीच लॉर्ड्स पर पुरुष टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था। इस मैच के पूरे 142 सालों के बाद महिला टेस्ट क्रिकेट का पहला मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड टीम को हार मिली।

भारत के युवा प्रतिभाओं ने जीता स्वर्ण

कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड (आईपीएचओ) 2026 में भारतीय दल ने स्वर्ण पदक जीता है। इस दल में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल थे। भारतीय दल को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हमारे युवाओं का शानदार प्रदर्शन!" उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हमारे युवा शक्ति की असीमित क्षमता के साथ ही विज्ञान एवं अनुसंधान के प्रति उनके जुनून का एक और उदाहरण प्रस्तुत करती है।

X

Narendra Modi
@narendramodi

बाबा बर्फानी के दर्शन से जुड़ी श्री अमरनाथ यात्रा हमारी आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय है। मेरी कामना है कि शिवभक्तों की यह यात्रा हर तरह से सुरक्षित और मंगलमय हो! इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए पांच संकल्पों से जुड़ा मेरा यह पत्र...

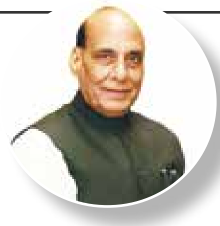

Rajnath Singh
@rajnathsingh

महादेव के सभी भक्तों एवं श्रद्धालुओं को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

देवाधिदेव महादेव एवं बाबा बर्फानी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह दिव्य यात्रा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करे। भगवान शिव से प्रार्थना है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सफल हो।

हर-हर महादेव

Amit Shah @AmitSh...

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का आधार है। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को नई ऊर्जा और विस्तार मिला है। चाहे सहकारिता विश्वविद्यालय हो, आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र हों या नए क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण हो, यह प्रयास किसानों, महिलाओं, छोटे उद्यमियों और श्रमिकों को सशक्त बनाते हुए "सहकार से समृद्धि" के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है।

Nitin Gadkari

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ₹4850 करोड़ के निवेश वाली 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

#PragatiKaHighway #GatiShakti #KanpurLucknowExpressway

Jyotiraditya M. Scindia @JM_Scindia

A rare sighting of Cyananthus hookeri blooming in Arunachal's Tawang after 158 long years...

Our Northeast is a living treasure trove of biodiversity, where nature continues to reveal its wonders. Such rediscoveries remind us of the region's unparalleled ecological wealth and the importance of preserving it.

Jagat Prakash Nadda
@JPNadda

World Population Day underscores the importance of voluntary family planning, informed choices, and healthy families as the foundation of inclusive and sustainable development.

This year's theme, "Healthy Timing and Spacing of Pregnancies for the Well-being of Mother & Child and planned parenthood" and the campaign slogan "जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने सशक्त और खुशहाल" reinforces the need to improve maternal and child health through informed reproductive choices and quality family planning services.

बड़ी रणनीतिक जीत: रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग का संकल्प

भारत को ऑस्ट्रेलिया देगा यूरेनियम, ऊर्जा से सुरक्षा तक बड़ी साझेदारी

मेलबर्न से मोदी का संदेश

'मदद में नहीं देखते पासपोर्ट का रंग'

शिखर वार्ता के प्रमुख फैसले

यूरेनियम समझौता क्यों अहम?

अब न्यूजीलैंड में एफडीए की बारी

मोदी ने लक्सन को दी हॉकी स्टिक, अल्बनीज को कॉफी बॉक्स

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को उत्तराखंडी टोपी भी दी, सुषियांतों को खास चाय का तोहफा

भारत दुग्ध उत्पादन में पहले और मोबाइल में दूसरे स्थान पर: मोदी

इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में भारतीय छात्रों का जलवा

जीते स्वर्ण पदक, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई

हाइड्रोजन ट्रेन: कम दूरी की यात्रा में नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी

मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, आतंकी शिविरों पर की गई कार्रवाई पर गर्व

ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देख ली भारत की ताकत: नरेंद्र मोदी

भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदार, बढ़ाएंगे रक्षा सहयोग, व्यापार लक्ष्य 35 हजार करोड़

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस

7 अगस्त

समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक

भारत का हथकरघा क्षेत्र राष्ट्र की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आर्थिक प्रतिरोध के रूप में स्वदेशी उद्योगों, खासकर हथकरघा का समर्थन किया। हथकरघा कारीगरों की इस विरासत के सम्मान और प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया। तब से यह दिवस हर साल बुनकर समुदाय का सम्मान करने, भारत की हथकरघा विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के सामूहिक संकल्प की दिलाता है याद...

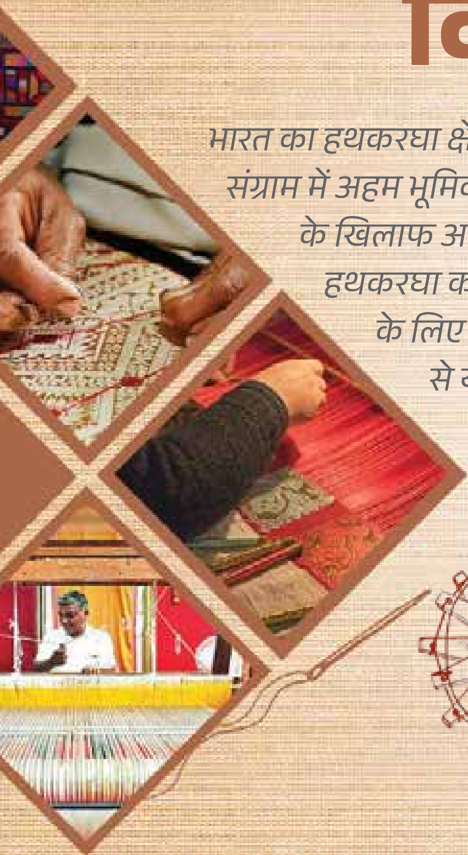

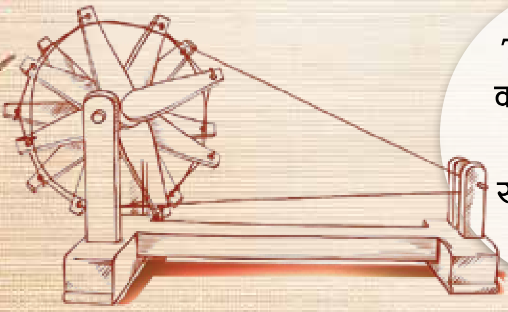

7 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा **12वां** राष्ट्रीय हथकरघा दिवस।

हमें अपने देश भर में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व है। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी कद्र करते हैं और 'वोकल फॉर लोकल' के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया समाचार पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 1-15 अगस्त, 2026

आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 20 जुलाई 2026, कुल पृष्ठ-46)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो,
सूचना भवन, द्वितीय तल,
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित